म्यांमार की चीन पर बढ़ती निर्भरता

लेखक - राजीव भाटिया (म्यांमार में पूर्व राजदूत)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

23 जनवरी, 2020

"म्यांमार के पास बीजिंग के साथ संबंधों को संतुलित करने में मदद करने वाले मित्र राष्ट्रों की कमी है।"

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले हफ्ते म्यांमार की राजकीय यात्रा इस क्षेत्र के बदलते भू-राजनीति का एक सबसे नवीनतम संकेत है, जो पश्चिम और उसके सहयोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसका वास्तविक महत्त्व हस्ताक्षरित 33 समझौतों में प्रतीत होता है।

जहाँ एक तरफ राष्ट्रपति शी ने इस दक्षिणी पड़ोसी देश में आने में काफी समय लिया, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के शीर्ष नेताओं द्वारा नियमितता के साथ बीजिंग की यात्रा की जाती रही है। इससे पहले उप-राष्ट्रपति के रूप में, इन्होंने 2009 में म्यांमार का दौरा किया था और एक चीनी राष्ट्रपति द्वारा अंतिम यात्रा 2001 में की गई थी। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को द्विपक्षीय संबंधों की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आदर्श अवसर के रूप में आँका गया है।

बर्मा (म्यांमार का पिछला नाम) के पहले प्रधानमंत्री यू नू ने इस क्षेत्र में अपने देश की स्थिति को 'कैक्टस के बीच एक कोमल लौकी' के रूप में दर्शाया था, फिर इसने स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता की नीति को चुना। अब सवाल उठता है कि क्या चीन के राष्ट्रपति को दिए गए रेड-कार्पेट ट्रीटमेंट से यह पता चलता है कि आज के म्यांमार ने संयुक्त रूप से आंग सान सू की और सेना के नेतृत्व के साथ अपनी राह ढूँढ ली है?

वर्तमान स्थिति इसी बात की ओर इशारा करती है कि म्यांमार ने अपनी राह चुन ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देखा जाये तो 2012 के बाद से (जब बराक ओबामा म्यांमार का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे) एक ऐतिहासिक तालमेल की शुरुआत की हुई थी, चीजें काफी बदल गयी हैं। पूर्व नेता राष्ट्रपति थीन सीन ने अमेरिका-चीन खेल को निपुणता के साथ खेला था, लेकिन वर्तमान नेतृत्व रोहिंग्या संकट और अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण, ये बीजिंग के करीब जाने के लिए मजबूर हैं।

परिणाम

18 जनवरी को जारी संयुक्त बयान में दावा किया गया है कि "व्यापक रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक समझ से उपजी दोनों देशों के बीच स्थायी दोस्ती में एक नए अध्याय की शुरुआत की गयी है।" यह "म्यांमार-चीन समुदाय के साथ एक साझा भविष्य को दर्शाता है।" "शासन में अनुभव" के आदान-प्रदान को गहरा किया जाएगा और रणनीतिक संचार को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, दोनों सरकारों ने 2 + 2 उच्च स्तरीय परामर्श का अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसमें दो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं।

यात्रा से पहले और उसके दौरान चीन ने जो कुछ भी कहा, वह इस बात की पुष्टि करता है कि चीन और म्यांमार के बीच पारंपरिक 'पाउक-फाव' (भाईचारे का) संबंध अब पूरी तरह से बेहतर हो चुके हैं। हालाँकि, इसमें एक स्पष्ट शर्त यह है कि संबंध न केवल सरकारों बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भी होना चाहिए। श्री शी ने जोर दिया कि लक्ष्य 'द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया खाका' तैयार करना है।

नि:संदेह व्यापार और निवेश से परे जाने वाले संबंधों के आर्थिक आयाम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन वर्षों से म्यांमार का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

(BRI) के एक महत्त्वपूर्ण घटक में प्रस्तावित चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे (CMEC, सीएमईसी) को वास्तविकता में बदलने के लिए एक निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

जैसा कि यात्रा के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर और चर्चा के माध्यम से सीएमईसी के तीन स्तंभों को समेकित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: Kyaukphyu विशेष आर्थिक क्षेत्र, चीन-म्यांमार सीमा आर्थिक क्षेत्र, और यांगून शहर का नया शहरी विकास। श्री शी ने कहा कि, मूल दृष्टिकोण 'दोनों लोगों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए' कनेक्टिविटी, बिजली, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, वित्त और आजीविका जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

चीन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रोहिंग्या मुद्दे पर अपनी कठोर स्थिति के कारण म्यांमार सरकार इस समय गहन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, लेकिन इसे चीन का पूर्ण समर्थन प्राप्त रहेगा। बीजिंग ने खुद को म्यांमार के वैध अधिकारों, हितों और राष्ट्रीय गरिमा के महान रक्षक के रूप में तैनात किया है, वो भी उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) म्यांमार की सेना के खिलाफ नरसंहार के आरोपों पर फैसला सुनाने वाला है। जैसा कि म्यांमार के लोगों का कहना है कि कुछ चीनी परियोजनाओं के खिलाफ उनकी शिकायतों को संबोधित किया जा रहा है, एक अनिर्दिष्ट समझौते के साथ विवादास्पद मित्सितोन बांध परियोजना को अभी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

अन्य निहितार्थ

म्यांमार के शीर्ष तीन नेताओं (राष्ट्रपति विन माइंट, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और कमांडर-इन-चीफ मिन आंग ह्लाइंग) के साथ विचार-विमर्श पर पर्याप्त समय बिताने के लिए श्री शी की पहल ने एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है। पिछले प्रयासों के बावजूद यह नेतृत्व जातीय सामंजस्य या संवैधानिक सुधार और पूर्ण लोकतंत्र पर जोर देने में विफल रहा है।

चीनी पक्ष यथास्थिति के साथ सहज लग रहा है और बाहरी चुनौतियों को देखते हुए इसे जारी रखने की सलाह दे सकता है। यह अच्छी तरह से एनएलडी सरकार और उसके सैन्य सहयोगियों के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र को आने वाले वर्षों में चुनावों में भाग लेना है। जब तक सुश्री सू की पूर्ण रूप से लोकतंत्र लाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करती हैं, तब तक उनकी सत्ता में वापसी की संभावना बहुत कम है।

तटस्थता और स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति म्यांमार के पारंपरिक झुकाव के बावजूद इसके पास मित्र देशों की कमी है जो इसे चीन के साथ संबंध को संतुलित करने में मदद कर सकें। अमेरिकी, यूरोपीय संघ (ईयू) और जापान इस भूमिका को निभाने में असमर्थ या अनिच्छुक या दोनों हैं। द इरावदी के संपादक क्यव जॉ मोए का दावा है कि 'पाउक-फाव' संबंध 'राजनीतिक शब्दजाल से परे नहीं है।' फिर भी यह निश्चित है कि म्यांमार की चीन पर निर्भरता नाटकीय रूप से बढ़ेगी। देश को अधिक चीनी पर्यटकों, परियोजनाओं, कंपनियों, उत्पादों और 'देश भर में चीनी राजनयिकों' के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए।

भारत पर प्रभाव

हाल के महीनों में भारत के आसपास की स्थिति ने प्रतिकूल मोड़ लिया है। चीन-पाकिस्तान संबंधों के समेकन की सामान्य पृष्ठभूमि के खिलाफ, श्री शी की नेपाल यात्रा, म्यांमार में उनके रणनीतिक लाभ और श्रीलंका के राष्ट्रपति की आगामी यात्रा एक विस्तृत पैटर्न का हिस्सा है। यह दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीति की असफलताओं और चुनौतियों में से एक है। यह भारत के लिए बेहतर विदेश नीति, गहन चिंतन और व्यापक विचार-विमर्श का आह्वान करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा हिंद महासागर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक शाखा है।
2. म्यांमार को रोहिंग्या मुद्दे पर चीन ने समर्थन दिया है।
3. हाल ही में चीन और म्यांमार के राजनयिक संबंधों की 71वीं वर्षगाँठ मनाई गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) केवल 3 (d) 1 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. The Sino-Myanmar Economic Corridor is a offshoot of the Belt and Road Initiative in the Indian Ocean..
2. China has supported Myanmar on the Rohingya issue.
3. Recently the 71st anniversary of diplomatic relations between China and Myanmar has been celebrated.

Which of the above statements are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) Only 3 (d) 1 and 3

नोट : 22 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: नेपाल के बाद चीन के म्यांमार के साथ सम्बन्धों में आती नजदीकी के क्या क्षेत्रीय निहितार्थ हो सकते हैं? भारत पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

What are the regional implications of China's proximity to Myanmar after Nepal? What could be its impact on India? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।